

संपादकीय

कनाडा को खरी-खरी

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में शामिल होने गये विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस दौरे में जहाँ राजनय की गरिमा को बनाये रखा, वहीं मौका मिलने पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कनाडा की भारत विरोधी नीति को बेनकाब करने का सार्थक प्रयास किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कनाडा का नाम न लेकर निज्जर प्रकरण से उपजे विवाद में परोक्ष रूप से अपनी बात कही। लेकिन न्यूयार्क में भारत में अमेरिकी राजदूत रहे केनेथ जस्टर के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में एस.जयशंकर ने वैशिक जगत को कनाडा के आरोपों के बाबत बताया कि ऐसा काम करना हमारी सरकार की नीति नहीं है। साथ ही साफ कह दिया कि कनाडा अलगावावादियों के लिये उर्वा भूमि बना हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने कनाडा से स्पष्ट कहा कि अगर आपके पास अपने आरोपों से जुड़ी कोई खास जानकारी है तो हमें उपलब्ध कराएं। इस अवसर का उपयोग करते हुए जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो के मंसूबों को बेनकाब करते हुए कहा कि कनाडा में पृथकतावादी तत्वों से जुड़े संगठित अपराधों के तमाम मामले प्रकाश में आए हैं। जिन पर कई बार कार्रवाई के बाबत कनाडा सरकार को कहा गया है। इस बात के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध कराये गये थे कि कनाडा की धरती से तमाम संगठित अपराध संचालित किये जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जयशंकर ने दुनिया को यह अहसास कराने का प्रयास किया कि कनाडा सरकार की नाक के नीचे सुनियोजित ढंग से अलगावादी कार्रवाईयां चल रही हैं। ऐसे तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला तक किया है। इतना ही नहीं भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गईं। विदेश मंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री के बयानों के आलोक में कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देकर भारत की

राजनीति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। सही मायानों में भारत—कनाडा के रिश्तों में आई कड़वाहट की हकीकत बताने में एस.जयशंकर सफल रहे। वहीं, यूएन सम्मेलन में भी विदेश मंत्री ने कहा कि वे दिन चले गये हैं जब दुनिया के कुछ बड़े राष्ट्र अपनी सुविधा के लिये एजेंडा तय करते थे और फिर शेष दुनिया को उस पर चलने के लिये बाध्य करते थे। दरअसल, टूटों के आरोपों के बाद कनाडा भी अलग—थलग पड़ा नजर आ रहा है। दरअसल, दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों को भी उभरते भारत के महत्व का अहसास है। जैसे कनाडा अमेरिका का निकट का सहयोगी है, उस हिसाब से अमेरिका भी उसके आरोपों के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। दरअसल, जिस खुफिया साझेदारी के संगठन फाइव आइज की सूचना को टूटों आधार बना रहे थे, उस इंटेलिजेंस अलायंस के सहयोगी अमेरिका, आरट्रेलिया, ब्रिटेन व न्यूजीलैंड का मुख्य समर्थन कनाडा को नहीं मिल पाया। यह भारत की मौजूदा वैश्विक छवि के चलते ही हुआ। यह भी कहा जाता रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने भी इस बाबत जानकारी साझा की थी। बहुत संभव था कि यदि जानकारी पुख्ता होती तो अमेरिका के तेवर तीखे होते। इस बाबत पूछे जाने पर एसद जयशंकर ने दो—टूक जवाब दिया कि हम न फाइव आइज का हिस्सा हैं और न ही एफबीआई का, जो इस बाबत जवाब दे सकें। विदेश मंत्री ने कहा कि निज्जर प्रकरण में कनाडा की तरफ से कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गये हैं। दरअसल, इससे पहले राजनयिक क्षेत्रों में कहा जा रहा था कि विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कनाडा को संदेश देना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि तीसरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत हमेशा से ही इस मंच का उपयोग वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिये करता रहा है। जयशंकर ने महासभा के जरिये साफ कह दिया कि दुनिया की बड़ी राजनीतिक ताकतें हिंसा, उग्रवाद व आतंकवाद पर प्रतिक्रिया अपनी राजनीतिक सुविधा से तय करती हैं। वैश्विक मंच से विदेश मंत्री ने हाल की भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नई दिल्ली के जी—20 सम्मेलन से हासिल की गूंज आने वाले दशकों में सुनाई देगी। हम विश्व मित्र के रूप में उपस्थित हैं।

आया चनावी याग्राओं का मौसम

भारत अब पूरी तरह चुनावी मुद्रा में आ चुका है। दिसम्बर महीने तक पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम में संभवतः चुनाव आ जायेंगे और उसके बाद अगले साल के अप्रैल महीने से लोकसभा के चुनाव शुरू हो जायेंगे। इन चुनावों की तैयारी हालांकि दो स्तरों राज्य व देश रस्तर पर करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी पार्टी कांग्रेस व झटिया गठबन्धन ने करनी शुरू कर दी है। पिछले तीस वर्षों के भीतर देश की राजनीति में जन यात्राओं का प्रवलन जिस तरह बढ़ा है उससे राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति में अन्तर भी देखा जा सकता है। पहले जहां राजनीतिक दल जनसभाओं पर जोर देते थे वहीं अब यात्राओं पर भी बराबर का जोर देने लगे हैं। इस परंपरा को हम लोकतन्त्र को अदिकारिक लोकमूलक बनाने की विश्वा में भी हक सकते हैं क्योंकि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने अपनी 'भारत—जोड़ा यात्रा' से सिद्ध कर दिया कि सीधे जनता के सम्पर्क में आने पर सुन्त जन विमर्शों को भी खड़ा किया जा सकता है। उनकी इस यात्रा की सफलता ने देश के दूसरे भाग—जैसके दलों को भी ऐसा दिया है। उनकी यात्रा

यात्रा एं चुनावी मौसम में करने का प्रतिफल भी तुरन्त ही प्राप्त है जिसे देखते हुए केन्द्र में सत्तारुद्ध भाजपा पार्टी ने अपनी मंसूबों की जन-कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना शरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को फैसला किया था ये यात्रा एं लोकसभा चुनावों से पहले अक्षर या नवम्बर महीने से इनकी जायेंगी। दूसरी तरफ राजस्थान राज्य के चुनावों के सन्दर्भ में राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पूरे सूचे की तरह हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा मिशन-2030 के लक्ष्य साथ लगातार नी दिन तक करेंगे। गहलोत का लक्ष्य है कि राजस्थान को 2030 तक भारत का नम्बर एक राज्य उनकी सदाचार में बना जायेगा। वेशक यह यात्रा राज्य के चुनावों से पहले ही पूरी की जायेगी। यात्रा का विमिनन कार्यक्रमों से जनता भली-भली परिचित हो सके। केन्द्र का भी लक्ष्य यही है कि मोदी सरकार ने भी योजनाएं चलाई हैं या आम लोगों को सुविधाएं दी हैं उनका गांव-गांव में प्रचार कराये जाये तो लोग इन योजनाओं से वीर्य उत्तराधीन रूप से जीवन का अधिकारी हों।

जाये। केन्द्र की योजनाएं लोगों की जरूरतों को देखते हुए बन हैं। इनमें प्रधानमन्त्री किसान, मुद्रा, जनधन, आवास व विधायक योजनाएं प्रमुख हैं। जबकि राजस्थान सरकार की गहलतें यह जोर इस बात पर होगा कि उनकी सरकार विधानसभा में कानून बनाकर गरीब व दलित और पिछड़े लोगों के हक में कौन से कानून बनाकर उन्हें जड़ से सशक्त किया है और हमेशा वह उनका अधिकार बना दिया है। इन कानूनों के बन जाने से किसान की जमीन बैंक अपना कर्जा वसूल करने के लिए खर्च न सकते और हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा जिससे वह निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करा है। वर्धी केन्द्र की भी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है जिसमें पांच रुपए तक का बीमा है। गहलते सरकार को किसानों की फसलों को कराने के लिए भी कानून बनाया है जबकि केंद्र की किसान फसल योजना भी लागू है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की ग्रामीण संवाद का लक्ष्य भी मादी सरकार द्वारा किये गये कार्यों के बारे में आगे बढ़ाव देने वाले और उन्हें व्यापकीय रूप से बढ़ाव देने।

ई गई वकर्मा त्रां में योगिन कौन दिए किसी ही कर होगा सकता लाख र बीमा र बीमा आत्राओं लोगों और भी चुनावी प्रचार ही है। फर्क सिर्फ यह है कि सरकार खुद गांवों में जाकर लोगों को अपने कार्यक्रमों के बारे में बतायेगी। केंद्र की ग्रामीण संवाद यात्राएं भारी शान वाली होंगी जिसके लिए 1500 रु तैयार किये जायेंगे जो जीपीएस प्रणाली से लैस होंगे और इनकी निगरानी डोन भी करते चलेंगे। ये रुप कुल ढाई लाख ग्राम पंचायतों में जायेंगे। ये यात्राएं कम से कम दो महीने तक चलेंगी। जाहिर है कि राजनीतिक दल ऐसी यात्राओं का आयोजन चुनावों में उत्तर लाप करने की दृष्टि से ही करती हैं भर्तु इसका लाप आम जनता के राजनीतिक रूप से सजग होने में भी होता है। यह सवाल भी अक्सर जनता के बीच राजनीतिक दल उठाते रहते हैं कि लोकतन्त्र में गरीबों या आम आदमी को सुधारण शासन की कृपा ही नहीं मिलतीं बल्कि कानून बनाकर उन्हें देने से हमेशा के लिए मिलती हैं क्योंकि इस व्यवस्था में आम आदमी की भागीदारी शासन में होती है। इसी वजह से कलोन्त्र में बड़ी सरकारों को जनता की भागीदारी से बड़ी सरकार को होता है। देश में राजनीतिक दलों की सरकारें अदल—बदल सकती हैं मगर जनता को मिले कानूनी अधिकार नहीं देती है जो उसके लिए जरूरी है।

वहीदा रहमान को फाल्के अवार्ड

बेहतरीन फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा एक ऐसी महिला का सम्मान है जिसने अपने जीवन में तरह-तरह की पाबंदियों, रुद्धिवादी विचारों और वर्जनाओं को तोड़ कर अपना मुकाम हासिल किया। वहीदा रहमान ने “आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इशारा है” को फिल्मी पर्ट पर जीकर महिलाओं को अभिव्यक्ति की नई जुबां दी। यद्यपि आज सिनेमा का स्वरूप बदल गया है। फिल्मी कहानियां भी पहले दौर जैसी नहीं रहीं। ग्लैमर की चकावांध से प्रगाहित फिल्मी संसार का कल्पना लोक बहुत विस्तार पा चुका है। लेकिन लोग आज भी वहीदा रहमान के निमाए गए किरदारों को भुला नहीं सके। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के चेंगल पट्टू में 1938 में तमिल मुस्तिरम परिवार में हुआ था और उन्होंने तेलुगू सिनेमा रोजुलु मर्री में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मी संसार में कदम रखा था। इस समय तक वह भरत नाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। युवा होने पर वह भारतीय सिनेमा की मुख्य गारा में आने के लिए प्रयास करती रही। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस दौर के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से हुई। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ ‘सी.आई.डी.’ में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की व्यापक फिल्म ‘प्यासा’ रिलीज हुई। यह फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम-प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रही। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म ‘कागज के फूल’ उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ दो अन्य फिल्में की थीं। इनमें वर्ष 1960 की ‘चौदहवीं का चांद’ और वर्ष 1962 की ‘साहिब बीबी और गुलाम’ प्रमुख हैं। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ दो अन्य व्यापक फिल्में ‘12 ओ’ क्लॉक’ (1958) और फुल मून (1961) भी हैं। फिल्मों में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को पांच सुपरहिट फिल्में दी थीं। ये फिल्में हैं—सी.आई.डी., सोलहवां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड।



सांसदी से विधायकी की भाजपायी उलटबांसी

भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों के नये दौर से गुजर रही है। दुनिया में नेतृत्व व जनप्रतिनिधि तत्त्व का विकास नीचे से ऊपर तकर होता है। कठिनपय अपवाहों को छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत या पार्श्व स्तर से विधायकी और फिर वहां से सासंसदी का रास्ता दिखलाया जाता है लेकिन भाजपा में उल्टी धारा बह रही है। इसी नवम्बर में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हैं। दोनों राज्यों के अब तक जितने उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है उनमें अनेक ऐसे हैं जो साफ तौर पर भाजपायी प्रयोग के गिनीपिण्ड बनाये जा रहे हैं। ये सांसद हैं लेकिन उन्हें विभिन्न विधानसभाई श्रीटों पर लड़ाया जा रहा है। कुछ तो मंत्री भी हैं। संसद सदस्यों को राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये उत्तराना साबित करता है कि भाजपा के पास मुद्दों के साथ-साथ चेहरों की भी कमी है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे पार्टी के सर्वैसर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके प्रमुख सहयोगी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुनियाजित चाल हो सकती है। देखना होगा कि यह कदम आत्मघाती साबित होता है या सफलता दिलाएगा। छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लें! यहां भाजपा बेहद कमज़ोर रिस्ति में है जहां 90 सीटों वाले सदन में उसके केवल 14 सदस्य हैं। यहां जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐसा लोगों से प्राप्त हो सकता है जिनमें

दुर्ग से लोकसमा में पहुंचे विजय बघेल को उनके चाचा व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन क्षेत्र से उतारा गया है। यह सीट दुर्ग की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। राज्यसभा के सदस्य रामविचार ने ताम सरगुजा क्षेत्र की रामानुजगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। रायपुर (शहर) सीट पर वर्तमान विधायक श्रीचंद सुंदरानी के साथ ही राजधानी के पूर्व महापौर सुनील सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा है जो इस वक्त रायपुर के संसद हैं। बिलासपुर सीट का लोकसमा में प्रतिनिधित्व करने वाले अरुण साव भाजपा के अध्यक्ष हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें बिलासपुर विधानसभा सीट से लड़ाया जा सकता है ताकि जीत की स्थिति में (जो वर्तमान परिदृश्य में दूर की कोड़ी है) उनका ओर्डीनी चेहरा काम आ सके और भूपेश बघेल का यह चुनाव प्रचार के दौरान जवाबी नाम भी हो। छत्तीसगढ़ की पिछले मुख्यमंत्रियों के समय से यह परम्परा बनी है कि जो पार्टी अत्यक्ष बहुमत दिला सके वही सीएम बन सकता है। 2003 में डॉ. रमन सिंह को सीएम पद इसलिये मिला था क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा जीती थी। ऐसे ही, भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जीत सके बाद उनकी इस पद की दावेदारी पर पार्टी हाईकमान की मुहर लगी थी। देखना होगा कि अरुण साव को टिकट थमाई जानी है या उन्हीं और अपना

ऐसा होता है तो क्या साव इस मीके को अपने लिये भुना पायेंगे? छत्तीसगढ़ की केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एकमात्र प्रतिनिधि। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की सांसद रेणुका सिंह हैं। क्या उहें भी छग में किसी सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये कहा जायेगा? अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालाकि



ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगुवाई में दर्जन भर से ज्यादा विधायकों को तोड़कर अपने पास में लेते हुए शिवराज सिंह व नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। इस लिहाज से यह पराजित पार्टी की सरकार है। इस बीच सरकार के खिलाफ जन आक्रोश तगड़ा है। वहाँ तीन तरह की भाजपा बतलाएँ



A large crowd of people holding orange flags with blue lotus symbols, likely at a political rally or event.



अभी काकी सीटों पर नाम घोषित होने बकाया है। खैर, मध्यप्रदेश का मसला और भी दिलचश्य है। पेंडिया भी। छग में तो भजपा के पास खोने के लिये कुछ नहीं है परन्तु मप्र में तो पूरी सरकार ही उसकी झोली से सरक सकती है। वैसे भी पिछली बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कमलनाथ के नेतृत्व में वह ऐसा सारन जनी भी पापन-

जाती है— शिवराज की, महाराष्ट्र की (सिंधिया) और नाराज कंपनी (असंतुष्टों की)। यहां पीम राजा शाह के लगातार दौरे हो रहे थे लेकिन हालत सुधरने के बावजूद नहीं ले रहे हैं। उल्टे, कांग्रेस सतत मजबूत हो रही है ज्योतिरादित्य के निकरतर्थ कर्म लोग कांग्रेस में लौट चुके हैं पिछले हफ्ते नीति जब आये थे उन्होंने पंजाब प्रिवेटर एवं

को विधानसभा सीटों की टिकटें थमाकर राज्य में भेज दिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्णीय सहित, जो कभी खुद ही प्रत्याशी करते थे, अब द्विदौर-1 से चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि मप्र भाजपा के समाने मुद्दों के साथ चेहरों के भारी अभाव के ही चलते भाजपा ने इतने संपर्कों को बताया है। अब भाजपा चुनाव लड़ेगी, यह सवाल भी बढ़ा है। स्थानीय चेहरे के अभाव में यह चुनाव अपने आप मोदी की छवि और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जायेगा। प्राज्य सामने दिख रही है, तो ऐसे में क्या मोदी अपना नाम राज्य इकाई को उधार देंगे? रणनीति की यह उल्टबांसी भाजपा के लिये बरदान बनती है या क्यामत— देवेन्द्र विजयवर्णी देंगे।

ह सवाल भी
वे हरे के अभाव
ने आप मोदी
कों के चेहरे पर
राज्य सामने
ऐसे में क्या
राज्य इकाई
रणनीति की
जपा के लिये
या कायमत—
देता।

एनारॉक की रिपोर्ट: सात शहरों में बिके रिकॉर्ड 1.20 लाख से ज्यादा मकान, बिक्री 36 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। लोक प्रेरणा होम लोन की स्थिति व्याज दरों के बीच मजबूत मांग से जुलाई से सितंबर के बीच सात प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री सालाना आधार पर 3.6% बढ़कर रिकॉर्ड 1,20,280 ब्लॉक पहुंच गई। एक साल पहले की समान अवधि में इन शहरों में 88,230 मकान बिके थे। संपर्क सलाइकर कंपनी एनारॉक के मुताबिक, कुल बिकी में मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और पुणे का कुल 51 फीसदी योगदान रहा। एनारॉक चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, जुलाई-सितंबर में सात शहरों में मकानों की खोज सत्र कीमत सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़ी। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 18 फीसदी की बढ़ोतारी देखी गई। उन्होंने कहा, आरबीआर के दो बार से रेपो दर को यथावत रखने से होम लोन पर व्याज दर स्थिर है। इससे बिक्री अच्छी बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर में 6 फीसदी का उछल जुलाई-सितंबर में दिल्ली और एनसीआर में मकानों बिक्री 6%



बढ़कर 15,865 इकाई पहुंची। मुंबई, महानगर क्षेत्र में बिक्री 46 फीसदी बढ़कर 38,500 इकाई पहुंच गई। बंगलूरु में बिक्री 29 फीसदी, पुणे में 63 फीसदी व फीसदी की तेजी रही।

चेन्नई में 42% व कोलकाता में 7 फीसदी की तेजी रही।

बिजनेस डायरी

भारत को 30 फीसदी महंगा कच्चा तेल देव रहा है रूस, अदाणी समूह ने बेचे 37,000 करोड़ के शेयर

नई दिल्ली। लोक प्रेरणा

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रूस भारत को महंगा तेल देव रहा है। इस समय वह पश्चिमी देशों को 60 डॉलर प्रति बैरल पर देव रहा है। कारोबारियों के मुताबिक, वैश्विक तेल बाजार में अपूर्ति कम होने व कीमतें बढ़ने से रूस नियावत का फायदा उठा रहा है। विशेषकों के मुताबिक, वही स्थिति रही तो देश में फेटोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह वस्तु समय से स्थिर बनी हुई है। तब भारत सत्रों में रूस से तेल खरीद रखा था, तब भी खुदरा बाजारों में फेटोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये के आस-पास थीं, और अब जब कच्चा तेल महंगा हो गया है, तब भी यह उसी भाव पर स्थिर है।

कारोबारियों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की जो तेल की इस समय कारोबारियों द्वारा खरीद रखी है, वह 80 डॉलर प्रति बैरल पर हो रही है। रूस में कच्चे तेल का घंटार कम हो गया है। उत्तराद्धन में भी कठोती की गई है। सुत्रों के मुताबिक, कठोती से भारतीय बंदरगाहों पर युगल के लिए छूट कम होकर 4-5 डॉलर प्रति बैरल पर है।

अब बैंक और डाक्टर्स अधिकारी भी मिलेगा एसीएस

न्यूज़ैशन सिस्टम के तहत 80 डॉलर प्रति बैरल पर हो रही है। ऐसे तेल की समान उत्पाद सभी बैंक शाखाओं व बांकोंमें भी मिलेंगे। पेंशन फंड रेजुलेटरी एंड डेक्लारेटरी अधिकारी के चेकरान दीपक मोहनी ने बताया कि इन्हें जल्द सभी बैंकों में उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, कुछ बैंक शाखाओं में यह अब भी मिल रहे हैं। मोहनी के मुताबिक, एसीएस वितरण के लिए एसीएस ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और बैंक प्रतिवेदियों को जोड़ा गया है। इससे गांवों व छोटे कस्बों के लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

13 लाख नए सदस्य जोड़ेंगे

मोहनी ने बताया, चालू वित्त वर्ष में निजी शेत्र से न्यू पेंशन सिस्टम (एसीएस) के तहत 13 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है। फिल्से तक वर्ष 10 में 10 लाख सदस्य जोड़े जाएंगे। इस साल 16 सितंबर तक एनपीसीसे से जुड़े लोगों की संख्या 1.36 करोड़ ही। अबल पेशन योजना के तहत ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ है।

अदाणी समूह ने बेचे 37,000 करोड़ के शेयर

अदाणी समूह के प्रोटोटरों ने इस साल जनरी से लेकर जून तक 37,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 87,000 करोड़ के शेयर वित्तिकारीकारी के प्रोटोटरों ने बेचे हैं जिनमें से 40 फीसदी अदाणी समूह ने बेचा है।

बीएसई पर सूचीबद्ध होगी विवा ट्रेडकॉम

विवा ट्रेडकॉम बीएसई पर सूचीबद्ध होगी। कंपनी आईआईआई में 51 रुपये प्रति शेयर का भाव से 9,99 करोड़ रुपये है। यह कपड़े और गारमेंट के नियाम और कारोबार से जुड़ी है। 2,000 शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

एनएसई के नियोक्ताओं की संख्या 8 करोड़ पार

एनएसई पर फिल्से के तहत नियोक्ता की संख्या 8 करोड़ जुड़े हैं। इसके साथ ही कुल नियोक्ताओं की संख्या 8 करोड़ के पार हो गई है। एनएसई ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के भी नियोक्ता जेनी से बाजार में आ रहे हैं।

खनिज उत्पादन में 10.7% वृद्धि

भारत का खनिज उत्पादन इस साल जुलाई में सालाना आधार पर 10.7 फीसदी बढ़ गया। भारतीय खान ब्यूरो (आईआईएस) के अस्थायी अंकितों के अनुसार, जुलाई, 2023 के लिए खनिज तंत्रजनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सुचकार 111.9 करोड़ रुपये है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 10.7 फीसदी अधिक है।

चालू वित्त वर्ष में 13.5% रु सकती है कर्फ़ की यदि

चालू वित्त वर्ष में जन की बढ़ि दर 13-13.5 फीसदी रु सकती है। हालांकि, आलू वित्त वर्ष में यह माझी सुधारक 13.5-14 फीसदी रु सकती है। किसिले के कहा, कुल कंज में थोक झूंक का विस्ता 60 प्रति शताब्दी 11-11.5% रु पा या गया है।

यस सिक्कोटीज रपर पांच लाख रुपया जुर्माना

ग्राहकों के टेक्टर्स और मार्जिन की गतिल जानकारी देने के मापदण्ड में सेवी ने यस सिक्कोटीज रपर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस क्रम को 45 दिनों में देना चाहा जाता है। सेवी, एनएसई, बीएसई और एमपीएस ने यसान मिलने पर संयुक्त रूप से यस सिक्कोटीज की जाँच की थी।

आईआईआईआईएड लॉब्यूर्ड को 1,729 करोड़ का जीएसटी भुगतान नोटिस

जीएसटी ईटिलिजेस इन दिनों कंपनियों को जमकर टैक्स नोटिस भेज रहा है। योगी कंपनी आईआईआईआईएड लॉब्यूर्ड जनरल ईटिलिजेस को बन्दु एवं सेवा कर (जीएसटी) ईटिलिजेस महानिदेशालय ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक टैक्स का कठित भुगतान न करने पर 1,729.8 करोड़ का टैक्स और कारण बताया जाने ने आईआईआईआईएड लॉब्यूर्ड को जो नोटिस भेजा है, वह को ईटिलिजेस प्रीमियम और री-ईटिलिजेस प्रीमियम पर जीएसटी भुगतान न करने से जुड़ा है।

एनारॉक की रिपोर्ट: सात शहरों में बिके रिकॉर्ड 1.20

व्यापार

मुद्रा: 17 देशों की मुद्राओं के मुकाबले रुपये का प्रदर्शन सबसे बेहतर

नई दिल्ली। लोक प्रेरणा

डॉलर की तुलना में लगातार गिरावट के बावजूद रुपये का प्रदर्शन 17 देशों की मुद्राओं के मुकाबले बेहतर रहा है। बैंक ऑफ ब्रॉडो द्वारा की मुताबिक, सितंबर में 17 देशों की तुलना में रुपये में सबसे कम 0.62 फीसदी गिरावट आई है। मैक्सिको की मुद्रा में सर्वाधिक 4.80 फीसदी गिरावट रही। रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर की तुलना में ताईवानी मुद्रा 1.21 फीसदी कमजोर हुई। मलेशियाई मुद्रा 1.46 फीसदी टूट गई। सिंगापुर डॉलर में 1.52 फीसदी गिरावट आई है। ब्राजीलियाई रील की तुलना में 2.18 फीसदी गिरावट आई है। तुक्केश लिरा में 2.29 फीसदी व मुद्रा 2.39% गिरावट में दर्ज की गई है। बालाकि, प्रमुख देशों में सिंप द्वांगकांग की मुद्रा 0.10



फीसदी मजबूत हुई है।

गिरावट क्यों और क्या होगा

असर

रुपया में गिरावट मूल रूप से गिरावट डैलर के मजबूत होने, कच्चे

तेल की कीमतों में उछल आने

विदेशों में खर्च करना या पढ़ाई करना या जारी होना आवश्यक है। आयोडी महंगा हो जाएगा। आयोडी अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में महंगी होनी चाही दी। अद्यतिंत वस्तुओं की ज्यादा कीमतें मिलेंगी।

पाकिस्तान ने फिर फैलाई चीन-सऊदी अरब के सामने झोली! मांगे 11 अरब डॉलर



सरकार आर्थिक पुनर्वास योजना पर काम कर रही है और यह योजना जल्द ही पाकिस्तान के सामने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल आईएमएफ प्रोग्राम का पालन करना उनकी प्राथमिकता है ताकि देश में आर्थिक स्थिरता रहे।

पाकिस्तानी नियंत्रित किसी देश के आर्थिक स्थिरता की मांगी जाएगी।

आईएमएफ

के बेलआउट कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने कुछ

सुधारों की लागू करने की बात

